

## SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



शोधसमागम

शोधसमागम शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग  
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू, झारखण्ड, भारत

### ORIGINAL ARTICLE



### Corresponding Author

शोधसमागम शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग  
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय,  
पलामू, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/01/2023

Revised on : -----

Accepted on : 27/01/2023

Plagiarism : 00% on 20/01/2023



Plagiarism Checker X - Report  
Originality Assessment

Overall Similarity: **0%**

Date: Jan 20, 2023

Statistics: 0 words Plagiarized / 1721 Total words

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.



शोधसमागम

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1980 के दशक की एक महत्वपूर्ण व राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक दृष्टि से गहरा प्रभाव भविष्य में डालने वाली घटना मानी गई। क्षेत्रीय एकीकरण की अवधारणा इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि में हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग नैसर्गिक तार्किक आधारशिला रखने के लिए की गई। 1980 के दशक में कई चुनौतियों से भारत और उसके पड़ोसी देश जूझ रहे थे। अपने क्षेत्रीय हितों को पूरा करने के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में पहल की जरूरत समझी गई।

शोधसमागम

शोधसमागम

शोधसमागम

बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने 2 मई 1980 को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ढाँचे की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इससे पहले उन्होंने 1977-80 के बीच भारत, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा कर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिससे आपसी सहयोग के कई मुद्दों को रखा गया। सार्क की स्थापना 7-8 दिसम्बर 1985 को ढाका के पहले सार्क शिखर सम्मेलन में की गई। इस संगठन की पहल ऐसे देशों को औपबंधिक रूप से एक साथ लाने की थी जो क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

सार्क आर्थिक सहयोग का मंच है। इसके जरिए राजनीतिक संबंधों में मजबूती मिलती है। इस मंच से जहाँ आपसी संबंधों को मजबूत कर सकते हैं वही सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आपसी मतभेद सुलझाने और उन पर खुलकर बात करने का मौका मिलता है। इस संगठन

का एकमात्र सदस्य देश भारत है जिसकी चार देशों के साथ साझा जमीनी सीमा है और दो देशों के साथ साझा समुद्री सीमा है।

क्षेत्रीय सहयोग को अनेक सामान्य निर्धारक तत्व सहयोग को प्रोत्साहन देते हैं। जाति, धर्म, भाषा सुभ्यता, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक समानताएँ विभिन्न देशों में पारस्परिक रूप से आदान-प्रदान और मेल-जोल होगा। इससे सामूहिक प्रयासों की सफलता अत्याधिक रूप से संभव होगी।

सार्क का मुख्य आधार क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना है, किन्तु समय के बदलने के साथ ही इसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन आए जो कि इसके सहयोग की भावना को प्रभावित की। 1983 के अगस्त में कुल नौ मुख्य बातें निर्धारित की गईं:

कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, विज्ञान, तकनीक व दूर-संचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग को शामिल किया गया।

धीरे-धीरे समय परिवर्तन से इसमें बदलाव शुरू हुआ यूरोपीय संघ, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता से दक्षिण एशिया के नेताओं ने कुछ नई चीजों को जानकर उससे सबक सीखा। आज के समय में यदि सार्क देश अन्य क्षेत्रीय संगठन से कुछ पाने की या लेने की अपनी इच्छा रख सके तो क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या चाहे वो गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, आपदा, अकाल, भूकम्प, सुनामी को एक प्रमुख समस्या जानकर चुनौतीपूर्ण रूप से साझेदारी कर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। लेकिन आज भी भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल में बारिश हो तो बिहार में इसका असर दिखता है। उसी प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादी से पीड़ित भारत इसका दुष्परिणाम उठाता है।

देखा जाए तो 21वीं सदी में आतंकवाद के वैश्विक तापन बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था की ओर आगे आ रहे हैं। दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता के साथ ही सामाजिक जीवन की विकृतियों को दूर करना है तो सार्क को इन चुनौतियों का सामना डटकर करना होगा।

## I kdZ dh mi yfçèk; k;

वर्तमान समय में सार्क एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो दक्षिण एशिया के नेताओं को एक साथ बैठकर सहयोग के साथ किसी भी बिन्दु पर विचार करने का स्थान देता है। इससे पहले दक्षिण-एशिया के नेताओं को अपनी समस्याओं को साक्षात् करने का कोई माध्यम नहीं था।

सार्क की स्थापना के शुरुआती वर्ष 1986 में बंगलौर में भारत-पाक शीर्ष नेताओं की औपचारिक मुलाकात में ही इसकी प्रासंगिकता दृष्टि-गोचर होने लगी। जब भारत-पाक तनाव में भारत के सैन्य अभ्यास बासटाक जो भारत पाक सीमा पर होने के कारण तनाव की स्थिति हो गई थी।

भारत-श्रीलंका तमिल मुद्दों पर सार्क के विदेश मंत्री सम्मेलन 1987 में सफल वार्ता की। सार्क के पर्यवेक्षक देशों के सदस्यता प्राप्त देशों में दक्षिण कोरिया, चीन, ईरान, अमरीका, यूरोपीय यूनियन हैं। सार्क के कार्यक्रमों में सार्क देशों ने एक पृथक वित्तीय संस्था के अधीन एक विकास कोष के साथ एक स्थायी सचिवालय के गठन पर सहमति प्रदान की तथा जिसमें सामाजिक संरचना को अधिक मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया।

1991 में भारत-पाक के नेताओं ने सार्क सम्मेलन में एक जनरल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके परिणामस्वरूप 1992 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक अनौपचारिक बातचीत दावोस में हुई जिसमें पाकिस्तान सरकार ने JKLF को सीमा नियंत्रण के आर-पार सीजफायर को रोकवाने में सफलता पाई।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) में परिवर्तन के लिए SAPTA पहला कदम था। समझौते में शामिल राज्यों के बीच पारस्परिक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्द्ध व्यापार संबंधी

बाधाओं को दूर करना तथा अनुबंधित राज्य के क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के सीमा-पार आवाजाही को सुसाध्य बनाना, मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना तथा राज्यों के आर्थिक विकास के स्वरूप और स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समान लाभ के अवसर सुनिश्चित कराना।

12वें शिखर सम्मेलन में 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के समझौते को प्रस्तुत किया गया। मुक्त व्यापार के निर्माण की संरचना तैयार की गई जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव की 1.8 अरब आबादी शामिल थी। वर्ष 2012 के अन्त तक इस प्रदेश में व्यावहारिक रूप से सभी उत्पादों के व्यापार पर शुन्य सीमा शुल्क के साथ SAFTA के संरचनात्मक समझौते पर सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। सात सरकारों द्वारा समझौते की स्वीकृति पर 1 जनवरी 2006 को यह लागू हुआ।

### I kdZ ea I g; kx I ðèkú ds ekud

1. आर्थिक प्रतिद्वंदी के स्थान पर सहयोग की भावना को अपनाना होगा, मालों के आवागमन पर सस्ता ट्रांसपोर्ट, कम सीमा शुल्क आदि के उपायों को करना होगा।
2. क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग पर केन्द्रित हो। सूचना प्रणाली तथा दूर संचार को विकसित करना आवश्यक है जिससे वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की जा सके।
3. बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो, उदार ऋण की सुविधा का प्रबंध होना चाहिए क्योंकि व्यापार के लेन-देन के लिए वित्त आवश्यक होता है।
4. राजनीतिक तनाव के कारण संबंधों में निकटता नहीं आ पाती। तनाव के कारण भारी माँग होते हुए भी भारतीय वस्तुओं का पाकिस्तान में स्मगलिंग होता है।

### Hkfe dk dVko

खनन उद्योग भूमि के क्षरण/कटाव का दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण कारण है। पर्यावरणीय असुरक्षा और भूमि पुर्नद्धार के कारण समस्या गंभीर बनी हुई है।

### -f"k Økfr

हरित क्रांति के बाद भारत में मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन बढ़ा। बांग्लादेश चावल/धान, पाकिस्तान रुई के उत्पादन, श्रीलंका चाय व नारियल, नेपाल-भूटान मक्के के उत्पादन, मालदीव मत्स्य का उत्पादन बहुतायत करते हैं।

एक ही मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया है। यदि ये राष्ट्र चाहे तो कृषि से संबंधित अनुसंधान, मृदा अनुसंधान व कृषि शिक्षा के समान एक पाठ्यक्रम के द्वारा क्षेत्र की कृषि से जुड़े व्यापार व उद्योग में भारी उन्नति कर सकते हैं। क्षेत्रीय शांति हेतु न्युक्लियर हथियारों का नियंत्रण नहीं करना चाहिए। नाभिकीय पारदर्शिता को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर की स्थापना करनी चाहिए।

### ouka dh dVkĀ

वनों की कटाई से सबसे ज्यादा प्रभावित देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है। नेपाल भी ईंधन के उपयोग के लिए जंगल की लकड़ी पर निर्भर होने के कारण वनों पर दबाव बढ़ा है। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण भी वनों के नष्ट होने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

### I eqeh i kfj fLFkfr dh

समुद्री पारिस्थितिकी के रूप में देखा जाए जो प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में अनुमानतः 1800 टन पेस्टसाइड बंगाल की खाड़ी में गिरता है। समुद्री तटों पर अनियंत्रित, बेलगाम आर्थिक गतिविधियाँ के कारण कोरल रीफ लैगून आदि का क्षरण तेजी से बढ़ा है।

## तृतीय शोध लेख

जैविकीय वस्तुओं के द्वारा अवैध व्यापार को अन्तराष्ट्रीय स्तर बढ़ावा देने से बाजार में अच्छी कीमत जैव तत्वों पर मिलती है।

दक्षिण एशिया पर्यावरण कार्यक्रम सहयोग (SACEF) 1982 में इस संस्था की स्थापना की गई। इनके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लाना है:

- निर्माण क्षमता और जागरुकता को बढ़ाना।
- सूचना के आदान-प्रदान के लिए नई तकनीकों की स्थानान्तरण।
- सहयोगी प्रबंधन करना।
- पर्यावरण प्रबंधन में प्रशिक्षण और संस्थाओं का विकास।
- वन्यजीव का संरक्षण।

सार्क के संबंध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। विचार निराशावादियों का है जो इसमें आन्तरिक और बाह्य कठिनाईयों को देखते हैं। इनका कहना है कि सार्क के सदस्य देशों के पास अपनी अर्थात् दक्षिण एशियाई पहचान नहीं है। इसके सदस्य देशों में विश्वास का संकट है। इसमें भारत की स्थिति बिग ब्रदर जैसी है। इस क्षेत्र के देशों में आपसी विवाद के कई मुद्दे हैं। यदि सार्क की भूमिका को सकारात्मक बनाना है तो आज भारत-पाकिस्तान को आपसी मतभेद को दूर करने की प्रबल आवश्यकता है। आपसी सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने के लिए सार्क को महाशक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रखकर राजनीतिक मंच बनाने की आवश्यकता है। अपनी साझेदारी, अनुभव व सहयोग के द्वारा सार्क देश सामूहिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

## संक्षेप

सार्क सम्पर्क सहयोग मित्रता में विकास के लिए परिवर्तन लाने का साधन बन सकता है। सार्क की क्षमता ताकत और विकास इसके सदस्य देशों पर निर्भर करती है। सार्क को बनने में बाधा डालने के लिए अन्तराष्ट्रीय राजनीति हमेशा इस बात के लिए जागरुक रहती है। लोगों की अपेक्षाएँ, जरूरतों को पूरा करना है तो क्षेत्र में परस्पर सम्मान और समझ विकसित करना होगा।

उद्देश्यों और भावनाओं को नष्ट करने में संदेह घृणा और भेदभाव जैसे मूल कारण हैं। राजनीतिक विकास में सहयोग करने के लिए तकनीकी सहयोग, व्यापार का सरलीकरण आदि है जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आर्थिक वैश्विक समृद्धि की ओर ले जाएगा।

धर्म, संस्कृति, सामाजिक और नस्लीय समानता आपसी लगाव के महत्वपूर्ण तत्व हैं। सामाजिक समस्या सकारात्मक विकास को बाधित करती है। सार्क सदस्य देशों को अब इस बात का चयन करना है कि विकास तथा विभिन्न विचारधाराओं से मुक्त समाज विरोध कार्यकलापों को दक्षिण एशिया में एक ऐसा स्थान दे जो इसके कार्यक्रमों तथा कार्यों को करने वा आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो।

## संदर्भ

1. फड़िया बी. एल., *अन्तराष्ट्रीय राजनीति भारत और सार्क*, साहित्य पब्लिकेशन, पृ0सं0 368।
2. विस्वाल तपन, *अन्तराष्ट्रीय संबंध*, ओरिएण्ट पब्लिकेशन, पृ0सं0 244।
3. धई यू. आर., *अन्तराष्ट्रीय राजनीति (सिद्धांत तथा व्यवहार)*, साहित्य भवनपब्लिकेशन, पृ0सं0 171।
4. सिंह मनोज, *समकालीन भारत का परिचय*, कीर्ति पब्लिकेशन, पृ0सं0 361
5. पंत पुष्पेश, *भारत की विदेश नीति*, मैकग्रो हिल एजुकेशन।

\*\*\*\*\*